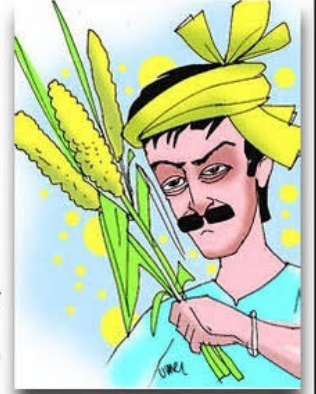


किसानों को बनाना होगा उद्योजक



■ अनुज गुप्त

दिल्ली. खाद्य तकनीक उद्यमिता व प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान यानि निफ्टम के कुलपति डा. अजित कुमार का कहना है कि किसानों को प्रशिक्षण देकर उद्योजक बनाना जरूरी है, क्योंकि जब वे गांव में ही छोटे-छोटे उद्योग लगाएंगे तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह वादा पूरा होगा, जिसमें वे किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं. इसीलिए वे अपने छात्रों को भी भावी उद्यमी के रूप में देखते हैं. सौ फीसदी प्लेसमेंट में इस संस्थान को पिछले 4 वर्षों में ही जो सफलता मिल गई है, उसके चलते सीटों की तुलना में अब 12 से 15 गुना अधिक आवेदक आ रहे हैं. सीटें बढ़ाने से पहले डा. कुमार वर्तमान शानदार उपलब्धियों को ही स्थिर कर लेना चाहते हैं. वैसे आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तकनीक व प्रबंधन दोनों का मिश्रण करके पूरे विश्व में सबसे अनूठा कोर्स चलाने वाले इस संस्थान ने गांवों को गोद लेने के अभियान में भी ज्यादा नाम कमा लिया है. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पिछले दिनों इसके लिए संस्थान की तारीफ की, जबकि संसद की कृषि संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2016-17 की अपनी 23वीं रिपोर्ट में तो यहां तक आग्रह कर लिया है कि ऐसे गांवों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाए और इसके लिए उसने सरकार से बजट बढ़ाने को भी कहा है. डा. कुमार कहते हैं, 'पिछले 4 साल से 18 राज्यों के 39 गांवों में विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत हमारे शिक्षक व छात्र 10 से 15 के 40 समूहों में जाकर उन गांवों में ही 10 दिन तक रहकर किसानों को तकनीक व प्रबंधन का प्रशिक्षण दे रहे हैं और मुद्रा योजना की मदद से अब उन्हें अपने छोटे उद्योग लगा पाने में भी हम मदद कर पा रहे हैं.' डा. एम.एस. स्वामीनाथन वाली समिति ने निफ्टम को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया है, क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने, स्वसहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने व ग्रामीणों को अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ पाने में भी संस्थान मदद कर रहा है.

“आईएस सेवा में रह चुके डा. कुमार ही जब खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में थे, तब वाजपेयी सरकार के समय 2002 में ही इस तरह का राष्ट्रीय संस्थान खोलने का विचार बना और 2006 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृत किया. पहले निदेशक व अब कुलपति के रूप में विश्व स्तर के इस संस्थान को उन्होंने ही खड़ा किया है. 500 करोड़ रूपए की लागत से दिल्ली के पास सोनीपत जिले के कोंडली में 100 एकड़ में फैले इस पूर्णतः आवासीय संस्थान के छात्रों ने दलहन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में दूसरा स्थान भी प्राप्त कर लिया है. 16 अगस्त 2012 को यहां का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था. आईआईटी दिल्ली से पीएचडी प्राप्त कुलपति से उनके दफ्तर में 'नवभारत' ने संस्थान के बारे में विस्तार से बातें कीं.”



निफ्टम के कुलपति डा. अजित कुमार से बातचीत

■ प्रश्न : ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को अत्याधुनिक व मजबूत बनाने में संस्थान की क्या भूमिका रहने वाली है?

कुमार : बाजार में खाने का जो भी सामान बिकता है, वह कहीं न कहीं कोई किसान पैदा करता है. ताजा सब्जियों व फल के साथ ही रीटेल ट्रेड में प्रोसेस किया हुआ खाद्य पदार्थ भी काफी बिकता है. सुरक्षित व स्वच्छ तरीके से भोज्य वस्तुओं को उपलब्ध कराने में फूड प्रोसेसिंग उद्योग की भूमिका आ जाती है.

किसानों को यदि तकनीकों की जानकारी दी जाए और बताया जाए कि वह अपने उत्पादों को कच्चे माल के रूप में ही न बेचें तो उनका भी लाभ हो सकता है. टमाटर केवल 2 रूपए किलो में वह बेच देता है, जबकि केचप बनकर वह 70 से 80 रूपए प्रति किलो में बिक जाता है. इससे किसानों की आय बढ़ेगी. प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं. यदि प्रसंस्करण कार्य से किसानों को जोड़ा जा सके तो वह दोगुना से भी अधिक बढ़ सकती है. खेती की व्यवहार्यता बढ़ेगी क्योंकि वेल्यू एडिशन से किसान की आमदनी बढ़ेगी तो पढ़े-लिखे युवा भी उससे जुड़ना चाहेंगे.

■ प्रश्न : रीटेल ट्रेड को भी इससे लाभ होगा?

कुमार : स्वाभाविक रूप से. छोटे व एमएसएमई उद्योगों को जब हाईजेनिक प्रैक्टिसेज से लैस किया जाए तो माडर्न रीटेल का महत्व बढ़ेगा. एफएसएसएआई के नियमों को लागू करके, पंजीयन कराकर व क्वालिटी में सुधार किया जाए तो छोटे उद्योगों के माल की स्वीकार्यता व बिक्री बढ़ेगी. हम तो किसानों को ही इस कार्य के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं. भारत चूंकि खाद्य उत्पादों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक व खपतकर्ता है, इसलिए इन कार्यों की यहां काफी गुंजाइश है. खाद्य वस्तुएं खराब होने से बचेंगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही उसका लाभ मिलेगा.

■ प्रश्न : शायद गांवों को गोद लेकर आप किसानों को प्रेरित कर रहे हैं?

कुमार : निफ्टम ने विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया है, जिसमें हमारे शिक्षक व छात्र 10 से 12 दिन तक गांव में ही रहकर किसानों से पूरी तरह जुड़कर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं. किसान ही जब उद्योजक बनेंगे, छोटे-छोटे उद्योग लगाएंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा और खुशहाली आएगी. हम तो उनसे कहते हैं कि छोटी पूंजी से पहले छोटे स्तर पर ही काम शुरू करें. जब मुनाफा दिखने लगे, तब धीरे-धीरे विस्तार करें. कई काम तो 5000 रूपए में भी शुरू कर ले रहे हैं. इस प्रोग्राम के लिए अब गांवों की संख्या बढ़ाने का आग्रह बढ़ रहा है. महाराष्ट्र में जलगांव जिले के कुरे, अहमदनगर जिले के पिंपरीगवली व कोल्हापुर जिले के यालगुड़ गांवों को भी हमने

गोद लिया है. वहां 4 वर्षों तक कार्य करके अच्छी कृषि पद्धतियों के बारे में भी बताते हैं.

■ प्रश्न : संस्थान के कोर्सों के प्रति छात्रों का रुझान कैसा रहा है?

कुमार : पहले साल से ही उत्साह दिखा. बी.टेक कोर्स की 120 सीटें थीं, जिस्के लिए 1500 आवेदन आए. जेईई परीक्षा से ही प्रवेश होता है. अगले साल से सीटें बढ़ाकर 180 की, जिस्के लिए 2000 से ज्यादा आवेदन आ रहे हैं. एम.टेक के 5 कोर्स हैं, हर में 18 सीटें हैं. 900 से अधिक आवेदन आए हैं. पीएचडी भी करा रहे हैं तो एमबीए भी शुरू किया है. इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज सुविधा का लाभ भी छात्र उठा रहे हैं. विश्वस्तरीय लैब, लाइब्रेरी, वाईफाई, जिमनाजियम आदि की सुविधा के अलावा छात्र व छात्राओं के हॉस्टल अलग-अलग हैं. इस कारण देशभर से छात्र-छात्रा काफी रुचि ले रहे हैं.

■ प्रश्न : प्लेसमेंट रिकार्ड कैसा है?

कुमार : शानदार और सौ फीसदी. बी.टेक का पहला बैच तो इस साल अभी निकल ही रहा है और 80 प्रतिशत का प्लेसमेंट हो चुका है. अगले 15 दिनों में बाकी इच्छुक छात्र भी सफल हो जाएंगे. एम.टेक के 2 बैच निकल चुके हैं और उन्हें 100 फीसदी सफलता मिली है. आईटीसी, डायर, पेप्सी, कोक आदि जैसी कंपनियां हाथोंहाथ यहां से पढ़ने वालों को ले रही हैं. अभी तक अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र गैर तकनीकी व गैरप्रशिक्षित लोगों के सहारे ही चलता रहा है, जिससे कार्यक्षमता 25 प्रतिशत तक कम हो जाती है. हमें लगता है कि उद्योग की जरूरत अधिक है, हम कम से कम 50 या 60 स्नातक कम निकाल रहे हैं.

■ प्रश्न : और, पैकेज कैसा मिल रहा है?

कुमार : अभी तक 10 लाख रूपए का अधिकतम पैकेज मिला है. लेकिन हर साल प्लेसमेंट के साथ ही पैकेज भी बढ़ रहा है और यही प्रगति रहने की संभावना है.

■ प्रश्न : उद्योग जगत से कैसे तालमेल बिठा पा रहे हैं?

कुमार : हम अपने पाठ्यक्रम उनसे चर्चा करके उनकी जरूरत के आधार पर ही तैयार करते हैं. उद्योगों की समस्याओं को लेकर ही रिसर्च भी यहां किए जा रहे हैं. निफ्टम इंडस्ट्रियल फोरम है जिसमें उद्योगों के 78 सदस्य साल में 2 बार बैठक करके तय करते हैं कि निफ्टम किस दिशा में जाए? रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल में उद्योग के साथ ही रिसर्च व एक्वैडेमिक्स के विशेषज्ञ भी हैं जो कि अगले 10 वर्ष का रोडमैप बना रहे हैं. इसके अलावा उद्योगों में काम कर रहे वर्तमान लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए हम अल्पकालीन कोर्स भी चलाते हैं. अभी ग्रैजुएट इंजीनियरों को कोल्ड चैन के लिए 3 हफ्ते की ट्रेनिंग कर रहे हैं.